Sudarshan Research Journal
Volume – 2, Issue - 2, February-2024
ISSN No: 2583-8792
Impact Factor: 3.179 (SJIF)

ई–गवर्नेंस के शिक्षा क्षेत्र में फायदों के बारें में रोहतक जिले के उच्च शिक्षा स्तर के विद्यार्थियों की अवधारणा : एक अध्ययन

कविता बैनिवाल[1]' डॉ. मिहिर रंजन पात्र[2]

जनसंचार विभाग गुरू जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा–125001

([1]जनसंचार विभाग, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, [2]संवाददाता लेखक)

सार

यह शोध पेपर शिक्षा के क्षेत्र में ई – गवर्नेंस के फायदों के बारें में विद्यार्थियों की अवधारणा पर आधारित है। शिक्षा क्षेत्र में ई–गवर्नेंस को लागू करना आज के तकनीकी युग की मांग भी है। इस शोध पेपर का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में ई–गवर्नेंस के फायदों के बारें में विद्यार्थियों की अवधारणा का अध्ययन करना है। शोध के अंतर्गत ई–गवर्नेंस से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के चरों जैसे कि कार्यकुशलता में बढोतरी, भ्रष्टाचार में कमीं, अधिकारीयों की जवाबदेही, शिक्षा में लोकतंत्र, सर्विस सेवा अधिकार, पारदर्शिता पर चयनित महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की अवधारणा का पता लगाया है। इसके अलावा यह भी पता लगया है कि उन्हें ई–गवर्नेंस से संबधित गतिविधियों की जानकारी किस माध्यम से प्राप्त होती है। काई–स्यौर सांख्यिकीय विधि से चरों के बीच सार्थक अंतर का पता लगाया गया है। विश्लेषण में यह पाया गया कि ई–गवर्नेंस के उपयोग से अधिकारीयों की जिम्मेंदारी बढ़ जाती है तथा भ्रष्टाचार में भी कम होता है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त सभी आश्रित चरों में सहमत व असहमत अवधारणाओं में सार्थक अंतर पाया गया है। विश्लेषण से पता चलता है कि न्यू मीडिया का उपयोग जानकारी हासिल करने के लिये सबसे ज्यादा किया गया जाता है, जोकि कुल का 36 प्रतिशत पाया गया है।

मुख्य शब्दः अवधारणा, ई–गवर्नेंस, मीडिया, न्यू मीडिया

I. परिचय

भारत में ई–गवर्नेंस 1970 के दशक में रक्षा, आर्थिक निगरानी, योजना, चुनाव, जनगणना और कर प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में स्वचालन और इंटरकनेक्शन के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने 1980 के दशक में जिला मुख्यालयों को आईसीटी के माध्यम से जोड़ा। 1990 के दशक के बाद से, ई–गवर्नेंस का विस्तार व्यक्तिगत विभागों में स्वचालन, इलेक्ट्रॉनिक फाइल प्रबंधन, सार्वजनिक शिकायत प्रणाली

और बिल और कर भुगतान को शामिल करने के लिए किया गया है। भारत सरकार ने 2006 में राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए सुलभ बनाना और किफायती लागत पर दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है।

भारत सरकार ई–गवर्नेंस परियोजनाओं में भारी निवेश करती है, एनडीएमसी परियोजना की लागत लगभग 20 मिलियन रुपये है। इन सेवाओं के नागरिकों के उपयोग का आकलन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार के पास एनडीएमसी क्षेत्र का 80: हिस्सा है और वह एकमात्र भूमि मालिक है। कुशल नगरपालिका सेवाएँ देश की आंतरिक छवि और सरकारी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं। एनडीएमसी परियोजना, जो 2001 में शुरू हुई और 2003 में पूरी तरह से चालू हो गई, सरकार द्वारा दी जाने वाली ई–गवर्नेंस सेवाओं के बारे में नागरिकों की धारणाओं का अध्ययन नहीं किया गया है।

हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 का उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, ई–गवर्नेंस सेवाओं को बढ़ाना है। ई–गवर्नेंस शुरू करने, सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल बनाने और प्रशासनिक मुद्दों में सुधार करने की पहल शुरू की गई है। राज्य सिविल सेवा केंद्र अभिविन्यास और पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी विभागों के कम्प्यूटरीकरण पर भी काम कर रहा है। राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम का लक्ष्य सभी ग्राम पंचायतों के लिए 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ वायर्ड और वायरलेस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य ने संचार एवं सूचना नीति लागू की है। इस परिवर्तन ने हरियाणा को डिजिटल रूप से सक्रिय ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदल दिया है।

हरियाणा राज्य शिक्षा के क्षेत्र में ई–गवर्नेंस को बढावा दे रहा है। हरियाणा स्कूल एमआईएस पोर्टल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिससे 20 लाख से अधिक छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश की सुविधा मिलेगी। पहले चरण में श्चेंज स्कूल एमआईएस पोर्टलश लॉन्च किया गया है, और अगले चरण में, प्रत्येक संस्थान, कार्यालय में स्वीकृत पदों, कर्मचारियों की कमी, पदों की कमी के लिए कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शिक्षक स्थानांतरण, एवं स्थानांतरण पोर्टल। इससे प्रशासनिक बोझ दूर होगा और शिक्षा विभाग को स्कूलों में शिक्षा मानकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तकनीकी शिक्षा 2006 से इंजीनियरिंग प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग परियोजना लागू कर रही है, 2007 से पेपरलेस प्रवेश परीक्षा और पेशेवर संस्थान प्रवेश प्रणाली का उपयोग कर रही है।[1]

हरियाणा राज्य के लिये भारत सरकार की एनआईसी की राज्य इकाई, आईटी विभाग और हाट्रीन तकनीकी पहलुओं में विभागों का समर्थन करने के लिए सहयोग करते हैं। विभिन्न समितियों के माध्यम से

[1] https://informatics.nic.in/uploads/pdfs/b7831060_1Haryana.pdf

Sudarshan Research Journal
Volume – 2, Issue - 2, February-2024
ISSN No: 2583-8792
Impact Factor: 3.179 (SJIF)

विभागीय आईटी योजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित, पारदर्शी और कुशल प्रणाली स्थापित की गई है। उनके प्रयासों से आईसीटी जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, नागरिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही आई है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई–गवर्नेंस में हरियाणा की छवि बढ़ी है।

यह शोध ई–गवर्नेंस के शिक्षा क्षेत्र में फायदे तथा इसके बारे में विद्यार्थियों की राय और उनकी अवबोधन पर आधारित है। इस शोध अध्ययन के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जायेगा कि क्या ई–गवर्नेंस शिक्षा में जो अपने फायदे देती है का लाभ विद्यार्थी उठा पा रहे है या नहीं। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन एनडीएमसी द्वारा दी जाने वाली ई–गवर्नेंस सेवाओं को अपनाने से विद्यार्थियों को होने वाले लाभों को मापने के लिए एक वैचारिक ढांचे का प्रस्ताव करता है। यह जांच करता है कि लिंग, आयु, शिक्षा, जैसी जनसांख्यिकीय विशेषताओं के आधार पर ई–गवर्नेंस लाभों के बारे में नागरिकों की धारणाएं कैसे भिन्न होती हैं। विद्यार्थियों के ई–गवर्नेंस महत्व को ध्यान में रखते हुये अध्ययन के लिए चुना गया है। हरियाणा सरकार ने ई–गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं, लेकिन उनकी सफलता कितनी मिली है और आगे की जांच की आवश्यकता है या नहीं शोध का विषय है।

II. साहित्य समीक्षा

- **Sharma, T., Mangalaraj, G., & Natarajan, V. S. (2016):** शर्मा टी व अन्य के द्वारा किये गये शोध से पता चलता है कि विश्व स्तर पर ई–गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी इंटरफेस का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में अपर्याप्तता, अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी और शासन प्रक्रियाओं की समझ उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती है। भारत के हरियाणा में एक अध्ययन में पाया गया कि निर्वाह स्तर के नागरिक आसानी से प्रौद्योगिकी–सहायता प्राप्त इंटरफेस सीखते हैं और सुविधा, उपयोग में आसानी, लागत और विश्वास की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। विपणन और ग्राहक सेवा प्रतिमान को अपनाकर, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और समावेशिता को बढ़ावा देकर, इन बाजारों को बेहतर सेवा दी जा सकती है और सामाजिक मुख्यधारा में एकीकृत किया जा सकता है।
- **Kumar, P., Kumar, D., & Kumar, N. (2014):** कुमार पी एवं अन्य ने अपने शोध पेपर में बताया कि भारत शासन में आईसीटी का उपयोग करते हुए पारंपरिक शासन से तकनीकी भागीदारी की ओर संक्रमण कर रहा है। सरकार ई–गवर्नेंस परिनियोजन में भारी निवेश कर रही है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता, सार्वजनिक धारणा, वैश्विक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बारे में सवाल बने हुए हैं। यह लेख इन मुद्दों को संबोधित करता है और भारत में सफल और टिकाऊ ई–गवर्नेंस तैनाती के लिए सुझाव देता है।

- **Yadav and Tiwari (2014)** यादव और तिवारी (2014) अपने अध्ययन "E-governance in India: Opportunities and Challenges", में दर्शाते है कि ई–गवर्नेंस द्वारा ऑनलाइन सेवा वितरण की उपयोगिता को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा स्वीकार किया गया है। यह पाया गया कि ई–गवर्नेंस परियोजनाएं पारदर्शिता को बढ़ाते हुए नागरिकों को दरवाजे पर सेवाओं की कुशल डिलीवरी प्रदान कर रही हैं। भ्रष्टाचार कम हो रहा है और यह लोगों के लिए बहुत सुविधाजनक है। लेखकों ने भारत में चल रही विभिन्न ई–गवर्नेंस परियोजनाओं का भी वर्णन किया है। दूसरी ओर अध्ययन में भारत में ई–गवर्नेंस कार्यान्वयन के सामने आने वाली चुनौतियों यानी कम साक्षरता, जागरूकता की कमी, कम ब्रॉडबैंड पहुंच आदि पर प्रकाश डाला गया है। लेखकों ने सुझाव दिया है कि सरकार को इन चुनौतियों से उभरने के लिए पहल करनी चाहिए।
- **Goel, S., Dwivedi, R., & Sherry, A. M. (2012):** गोयल एस व अन्य के शोध पेपर से पता चलाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र परिवर्तन में विकास दृष्टिकोण के लिए आईसीटी का उद्देश्य सेवा वितरण और सरकारी कामकाज में सुधार करना है। हालाँकि, कई स्थानों पर लागू होने पर कार्यान्वयन जोखिम बढ़ जाते हैं। यह अध्ययन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) में ई–गवर्नेंस कार्यान्वयन के मामले की जांच करता है और सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है। अध्ययन का उद्देश्य यह समझना है कि वांछित सफलता प्राप्त करने के लिए हुडा ने इन चुनौतियों को कैसे संभाला।
- **P. Muralidhran (2010):** पी. मुरलीधरन (2010) का अपने शोध 2010), "E-governance – A service delivery mechanism for effective administrative system", में कहना है कि आईसीटी ने लगभग सब कुछ जैसे काम करना, संचार करना, सीखना आदि में मौलिक परिवर्तन ला दिया है। लेखक की भविष्यवाणी है कि ई–गवर्नेंस नवीन परिणामोन्मुखी सार्वजनिक क्षेत्र के नेतृत्व के लिए अभूतपूर्व अवसर लाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। सरकारी उद्यम औद्योगिक समाज से सूचना समाज तक परिवर्तन ला सकता है। इसके बाद लेखक ने कहा कि ई–गवर्नमेंट ऑनलाइन सेवाएं सरकार और नागरिक, व्यवसाय और उसके कर्मचारियों के बीच क्रांति ला सकती हैं।

III. शोध के उद्देश्य

1. रोहतक जिले के महाविद्यालय के छात्रों का ई–गवर्नेस के बारे में जानकारी के माध्यम का पता लगाना।
2. चयनित महाविद्यालयों के छात्रों की ई–गवर्नेंस के शिक्षा क्षेत्र में लाभ के बारें में अवधारणा का पता लगाना।

IV. शोध विधि

शोधकर्ता ने यह शोध ई–गवर्नेंस के शिक्षा क्षेत्र में लाभ के बारे में रोहतक जिले के महाविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहें छात्रों की अवधारणा पर एक अध्ययन किया है। शोधकर्ता ने छात्रों के चयन के लिये रोहतक जिले के चार महाविद्यालयों को सुविघा पद्धति के आधार पर शोध के प्रदत हेतू जनसंख्या लिया है। ये चार महाविद्यालय इस प्रकार हैः–

1. पं. नेकी राम शर्मा राजकीय महाविद्यालय, रोहतक
2. मातुराम तकनीकी एवं प्रबंधन महाविद्यालय, रोहतक
3. गौड़ ब्राहम्न डिग्री महाविद्यालय, रोहतक
4. एस. जे. के. कॉलेज, रोहतक

उपर्युक्त महाविद्यालय में दो महाविद्यालय संस्था के अंर्तगत कार्य तथा एक महाविद्यालय राज्य सरकार के अंर्तगत आता है। प्रत्येक महाविद्यायल में से शोधकर्ता ने 75 विद्यार्थियों का चयन सुविधाजनक (कंविनियंट) प्रदत के रूप में किया है।

कुल 300 विद्यार्थियों को प्रदत के रूप में चुना गया है। प्रत्येक महाविद्यालय से पुरूष तथा महिला दोनों लिंग के विद्याथियों को चुना गया है तथा उनसे प्रश्नावली/स्क्डयूल के माध्यम से प्रश्नों के उतर जाने गये है। कुल 150 पुरूष तथा 150 महिला छात्रों को इस शोध में प्रदत के रूप में शामिल किया गया है। शोध पेपर में दोनों तरह के चर स्वतंत्र व आश्रित का अध्ययन किया गया है। आयु, कक्षा श्रैणी तथा लिंग को स्वतंत्र चर के रूप में तथा ई–गवर्नेस के शिक्षा क्षेत्र में लाभ/फायदों के बारें में जानकारी तथा अवधारणा को आश्रित चर के रूप में लिया है।

यह शोध एक संख्यात्मक शोध डिजाइन पर आधारित है। शाधकर्ता ने प्रतिशत तथा माध्यम सांख्याकीय विधियों का प्रयोग प्रदत के आंकलन हेतु किया है। इसके अतिरिक्त काईस्क्यौर (chi-square) का प्रयोग अलग–अलग श्रेणीयों के प्रदत में कोई महत्वपूर्ण सार्थक अंतर को मापने के लिये किया है। प्रदत के विश्लेषण हेतु एम.एस. एक्सल सॉफवेयर का प्रयोग किया गया है।

V. आंकड़ों का विश्लेषण व शोध परिणाम

आंकडों का विश्लेषण में शोधकर्ता ने उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण किया है। शोधकर्ता ने तालिका का निमार्ण तथा तालिकाओं का विवरण दिया है। विभिन्न चर के आधार पर तालिकाओं को निर्मित किया है तथा उनकी व्याख्या की है।

Sudarshan Research Journal
Volume – 2, Issue - 2, February-2024
ISSN No: 2583-8792
Impact Factor: 3.179 (SJIF)

तालिका 1. ई–गवर्नेंस के बारें में किस माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई –

चर	श्रेणी	इलैक्ट्रोनिक मीडिया	प्रिंट मीडिया	न्यू मीडिया, फेसबुक/वट्सएप	अन्य	कुल	Chi Square X^2	df	P value
लिंग	पुरूष	33 22.0	38 25.3	55 36.7	24 16.0	150	0.625	3	**0.89**
	महिला	35 23.3	34 22.7	53 35.3	28 18.7	150			
क्षेत्र	ग्रामिण	36 24.0	41 27.3	66 44.0	35 23.3	178	2.833	3	**0.417**
	शहरी	32 21.3	31 20.7	42 28.0	17 11.3	122			
आयु वर्ग	20 वर्ष से नीचे	29 19.3	36 24.0	60 40.0	16 10.7	141	13.95	6	**0.03**
	21 – 30	24 16.0	26 17.3	25 16.7	20 13.3	95			
	30 वर्ष से ऊपर	15 10.0	10 6.7	17 11.3	15 10.0	57			
शिक्षा	स्नातकौतर में	32 21.3	35 23.3	50 33.3	23 15.3	140	0.13	3	**0.987**
	स्नाातक में	36 24.0	37 24.7	58 38.7	27 18.0	158			
चयनित कॉलेज	पं0 नेकी राम राजकीय महाविद्यालय	17 11.3	19 12.7	25 16.7	14 9.3	75	7.773	9	**0.557**
	गौड़ महाविद्यालय	20 13.3	17 11.3	21 14.0	17 11.3	75			
	एस. के. महाविद्यालय	14 9.3	16 10.7	35 23.3	10 6.7	75			
	मातु राम तकनीकी एवं प्रबंधन महाविद्यालय	17 11.3	20 13.3	27 18.0	11 7.3	75			
	कुल	**68** 22.7	**72** 24.0	**108** 36.0	**52** 17.3	300			

स्रोत : फिल्ड सर्वे

तालिका 1 से पता चलता है कि 36. प्रतिशत उत्तरदाताओं ने फेसबुक तथा वट्सएप से ई–गवर्नेस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। 24 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से और 17.3 प्रतिशत ने अन्य स्रोतों से इस बारे में पता चला है। सबसे कम 17.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य स्त्रोतों के माध्यम से ई–गवर्नेस के बारे में पता चला है जबकि 22.7 प्रतिशत इलैक्ट्रानिक मीडिया से पता चला है।

अध्ययन में पाया गया कि 36.7 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाताओं ने न्यू मीडिया फेसबुक तथा वट्सएपं के माध्यम से ई–गवर्नेस के बारे में जानकारी प्राप्त की, जबकि 25.3 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। 22.0 प्रतिशत उतरदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त होनें के बारे में उत्तर दिया, और 16.0 प्रतिशत ने अन्य स्रोतों के माध्यम से ई–गवर्नेस के बारे में जानकारी प्राप्त

हुई है, उत्तर दिया। 33.3 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं को ई–गवर्नेस के बारे में जानकारी न्यू मीडिया से प्राप्त हुई, जबकि 18.7 प्रतिशत ने अन्य माध्यम से जानकारी प्राप्त होनें के बारे में बताया। 22.7 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। 23.3 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ई–गवर्नेस के बाने में जानकारी प्राप्त की।

तालिका 1 से पता चलता है कि 44.0 प्रतिशत ग्रामीण उत्तरदाताओं ने न्यू मीडिया को अपनी जानकारी का स्त्रोत बताया जबकि 27.3 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें ई–गवर्नेस के बारे में जानकारी प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। 23.3 ने अन्य स्रोतों के माध्यम से इस बारे में जानकारी प्राप्त की। जबकि 24.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया गया था। शहरी क्षेत्रों में, 28.0 प्रतिशत ने न्यू मीडिया के माध्यम से जानकरी प्राप्त की, वहीं 20.7 ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, तथा 21. 3 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की। 11.3 प्रतिशत ने शहरी उतरदाताओं ने अन्य स्रोतों के माध्यम से ई.–गवर्नेस के बारें में जानकारी प्राप्त की।

अध्ययन में पाया गया कि 20 वर्ष से कम उम्र के 40.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को न्यू मीडिया के माध्यम से ई – गवर्नेंस के बारे में जानकारी हासिल हुई, जबकि 24 प्रतिशत प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस जानकारी के बारे में जागरूक हुए। 19.3 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और 10.7 प्रतिशत ने अन्य स्रोतों के माध्यम से ई–गवर्नेस के बारे में जाना। 21 से 30 आयु वर्ग में अधिकांश उत्तरदाताओं 16.7 प्रतिशत ने न्यू मीडिया फेसबुक तथा वट्सएप के माध्यम से ई – गवर्नेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की, वहीं 17.3 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया तथा 13.3 प्रतिशत ने अन्य स्रोतों को अपनी जानकारी का स्त्रोत बताया। जबकि 16.0 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की। 30 से अधिक आयु समूह ने 11.3 प्रतिशत ने न्यू मीडिया को अपना जानकारी स्त्रोत बताया वहीं 6.7 प्रतिशत ने कहा की उन्हें इस बारे में सूचना प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। शेष 10.0 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा 10.0 प्रतिशत ने किसी अन्य स्रोत से जानकारी आने की सूचना दी।

अध्ययन में शैक्षिक योग्यता डेटा का विश्लेषण किया गया, जिससे पता चला कि 33.3 प्रतिशत स्नातकोतर कर रहें छात्रों नें न्यू मीडिया के माध्यम ये ई – गवर्नेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की वहीं इसी क्रम में 23.3 प्रतिशत ने स्रोत के रूप में प्रिंट मीडिया का उल्लेख किया, और 21.3 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस बारें में जानकारी प्राप्त की। अन्य स्त्रोत बताने वाले छात्रों का प्रतिशत 15.3 रहा। स्नातक के लिये शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में से 38.7 प्रतिशत ने न्यू मीडिया से जानकारी प्राप्त करने का उल्लेख किया, वहीं 24.7 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें यह जानकारी प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। 24.0 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके जानकारी हासिल की, वहीं 18.0 प्रतिशत ने किसी अन्य स्रोत का उपयोग किया।

विश्लेषण से पता चलता है कि पं. नेकी राम राजकीय महाविद्यालय में 16.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं

ने जानकारी न्यू मीडिया के माध्यम से प्राप्त की, जबकि 9.3 प्रतिशत ने अन्य स्रोतों को इसका श्रेय दिया। वहीं 11.3 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से सीखने और 12.7 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जानकारी हासिल करने का उल्लेख किया। गौड़ बाह्मन महविद्यालय में, 14.0 प्रतिशत उतरदाताओं ने कहा की उन्हें इस बारे मे जानकारी न्यू मीडिया से प्राप्त हुई, वहीं इसी कड़ी में 11.3 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया और 13.3 प्रतिशत उतरदाताओं ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ई–गवर्नेस बारे जानकारी की सूचना दी। 11.3 प्रतिशत उतरदाताओं ने अन्य स्त्रोत से यह जानकारी प्राप्त होने के संकेत दिये। एसके माहविद्यालय में, 23.3 प्रतिशत ने ई–गवर्नेस के बारे मे न्यू मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई, जबकि 10.7 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से ई–गवर्नेस बारे ज्ञान प्राप्त किया। 9.3 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी प्राप्त करने का स्रोत बताया वहीं 6.7 प्रतिशत ने अन्य स्रोतों का उल्लेख किया। मातु राम तकनीकी महाविद्यालय में, 18.0 प्रतिशत ने न्यू मीडिया के माध्यम से, 13.3 प्रतिशत ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, 11.3 प्रतिशत ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 7.30 प्रतिशत ने अन्य स्रोतों से ई–गवर्नेस बारे जानकारी प्राप्त की।

तालिका 2. *ई–गवर्नेंस के शिक्षा के क्षेत्र में फायदों के बारें में उतरदाताओं की अवधारर्णा–*

20 ई–गवर्नेंस की शिक्षा में उपयागिता		पूर्ण असहमत	असहमत	तटस्थ	सहमत	पूर्ण सहमत	कुल	Chi square sign (P value)
कार्यकुशलता में वृद्धि	n	2	5	10	56	227	300	0
	%	0.67	1.67	3.33	18.67	75.67		
भ्रष्टाचार कम करने में साहयक	n	5	12	20	65	198	300	0
	%	1.67	4.00	6.67	21.67	66.00		
अधिकारीयों की जिम्मेदारी में वृद्धि	n	8	10	15	98	169	300	0
	%	2.67	3.33	5.00	32.67	56.33		
सेवा का अधिकार सुनिश्चित करना	n	3	4	11	100	182	300	0
	%	1.00	1.33	3.67	33.33	60.67		
पारदर्शिता लाना	n	2	9	12	107	170	300	0
	%	0.67	3.00	4.00	35.67	56.67		
किसी प्रकार के बाहरी दबाव को कम करना	n	23	35	65	76	101	300	0
	%	7.67	11.67	21.67	25.33	33.67		
शिक्षा में लोकतंत्र का बढाना	n	1	5	45	96	153	300	0
	%	0.33	1.67	15.00	32.00	51.00		
कुल		44	80	178	598	1200	2100	

स्रोत : फिल्ड सर्वे

तालिक 2 के विश्लेषण से पता चलता है कि उतरदाताओं की ई–गवर्नेस के शिक्षा क्षेत्र में फायदों के बारें मे क्या – क्या अवधारणा है। ऑनलाइन सेवाएँ के जरिये जैसे ई–गवर्नेस लोगों को फायदे पहुंचा रही है उसी से संबधित प्रशनों का उतरदाताओं से पुछा गया और जानकारी का लिर्कट स्केल के माध्यम से मापा गया है। उसके बाद सहमत तथा असहमत के बीच में सार्थक अंतर काई – स्कवेयर टेस्ट के माध्यम से जाना गया है।

यदि सेवा प्रावधान में कार्य कुशलता की बात करें तो यह पाया गया कि 75.67 प्रतिशत उतरदाताओं नें पूर्ण सहमत पर अपना मत दिया। इसके बाद 18.67 प्रतिशत ने सहमत पर अपना मत दिया। 0.67 प्रतिशत पूर्ण असहमत तथा 1.67 प्रतिशत ने असहमत पर अपना उतर दिया। सेवा प्रावधान में पारदर्शिता से भ्रष्टाचार कम होता है प्रश्न के उतर में 66.0 प्रतिशत पूर्ण सहमत थे जबकि 21.67 प्रतिशत उतरदाता सहमत तथा 4.0 प्रतिशत ने असहमत प्रतिक्रिया दी। वहीं पूर्ण असहमत का प्रतिशत 1.67 रहा। अधिकारियों की जिम्मेंदारी और बढती है प्रश्न के उतर में 56.33 प्रतिशत ने पूर्ण सहमत पर अपना मत दिया जबकि इसी कड़ी में 32.67 प्रतिशत सहमत रहें। 3.33 प्रतिशत असहमत तथा 20.67 प्रतिशत उतरदाता पूर्ण असहमत पाये गयें। हालाकि 5.0 प्रतिशत उतरदाता तटस्थ भी पाये गयें।

राइट टू सर्विस के बारे मे प्रश्न के उतर में 60.67 प्रतिशत उतरदाता पूर्ण सहमत तथा 33.33 प्रतिशत उतरदाता सहमत पाये गयें, जबकि 1.33 प्रतिशत असहमत व 1.0 प्रतिशत पूर्ण असहमत उतरदाता पाये गये। इसी कड़ी में 3.67 प्रतिशत उतरदाता तटस्थ भी पाये गयें। ई – गवर्नेंस से पारदर्शिता आती है प्रश्न के उतर में पाया गया कि 56.67 प्रतिशत उतरदाता इस बात से पूर्ण सहमत थे जबकि 35.67 प्रतिशत सहमत थे। हालांकि 0.67 प्रतिशत उतरदाता पूर्ण असहमत व 3.0 प्रतिशत उतरदाता असहमत पाये गयें। चार प्रतिशत उतरदाता तटस्थ भी पायें गये।

शिक्षा क्षेत्र में बाहरी दबाव कम हो जाता है, प्रश्न के जवाब में यह पाया गया कि 33.67 प्रतिशत उतरदाता इस बात से पूर्ण सहमत थे जबकि 25.33 प्रतिशत सहमत थे। हालांकि 11.67 प्रतिशत उतरदाता असहमत व 7.67 प्रतिशत पूर्ण असहमत भी पाये गये। वहीं 21.67 प्रतिशत तटस्थ रहे। ई–गवर्नेंस से शिक्षा में लोकतंत्र को बढ़वा मिलता है के जवाब में पाया गया कि 51.0 प्रतिशत उतरदाता इस बात से पूण्र सहमत थे जबकि 32.0 प्रतिशत उतरदाताओं ने सहमत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं 1.67 प्रतिशत असहमत व 0. 33 प्रतिशत उतरदाता पूर्ण असहमत पाये गयें। इसी कड़ी में 15.0 प्रतिशत उतरदाता तटस्थ पाये गये।

VI. सारांश

अध्ययन में पाया गया कि विद्यार्थी लगभग सभी प्रकार के मीडिया का उपयोग जानकारी हासिल करने के लिये करते है। परंतु ई–गवर्नेंस से संबधित जानकारी प्राप्त करने लिये न्यू मीडिया का उपयोग सबसे ज्यादा किया गया है। यह कुल का 36 प्रतिशत पाया गया। सबसे कम प्रतिशत अन्य का रहा जोकि 17.3 प्रतिशत पाया गया। जानकारी को लेकर सभी प्रकार के मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया, इलैक्ट्रोनिक मीडिया तथा न्यू मीडिया व अन्य को लेकर केवल आयु वर्ग के अनाश्रित चर में ही सार्थक अंतर पाया गया। बाकी अनाश्रित चर जैसे लिंग, क्षेत्र, कक्षा और स्थान के लिये काई–स्कवायर पी का मान 0.05 से ऊपर पाया गया, जिससे यह साबित होता है कि इन चरों में विभिन्न मीडिया को लेकर कोई सार्थक अंतर नहीं है।

विश्लेषण से पता चलता है कि शिक्षा क्षेत्र में ई–गवर्नेंस लागू करने से कर्मचारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस

बारें में सहमत और असहमत दोनों की में एक सार्थक अंतर पाया गया है। काई–स्कवायर पी का मान 0.05 से कम है। ऑनलाइन सेवाएँ उच्च अधिकारीयों को दिखाई देती हैं, जिससे कर्मचारियों को समय पर कार्य पूरा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसमें दोनों स्तर पर जिम्मेंदारियां बढ जाती है। शिक्षा क्षेत्र में ई–गवर्नेंस सेवा प्रावधान में पारदर्शिता से भ्रष्टाचार कम होता है और उतरदाता ई–गवर्नेंस को एक सकारात्मक समाधान मानते हैं। इससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तथा शिक्षा क्षेत्र में लोकतंत्र और आशावाद बढ़ता है। कार्यकुशलता, भ्रष्टाचार में कमी दोनों चरों में उतरदाताओं की अवधारणाओं में सहमत व असहमत स्तर को लेकर एक सार्थक अंतर पाया गया है। काई–स्कवायर पी का मान 0.05 से कम है। उतरदाताओं को उम्मीद है कि सहमत और पूर्ण सहमत के अधिकत्म मूल्य के साथ ऑनलाइन सेवाएं शिक्षा क्षेत्र में इस हस्तक्षेप को ओर कम करेंगी। राइट टू सर्विस के बारे में उतरदाताओं की राय साकारात्मक पाई गई, अधिकत्म उतरदाताओं ने पूर्ण सहमत तथा सहमत पर अपना मत दिया हैं व सहमत और असहमत में पी का मान 0.05 से कम पाया गया है। इससे पता चलता है उतरदाता राइट टू सर्विस के बारे में एक साकारात्मक अवधारणा रखते है। अध्ययन से पता चलता है कि विद्यार्थियों में ई–गवर्नेंस प्रणाली का उच्च शिक्षा में उपयोग के फायदों के बारे में उच्च सकारात्मक अधारणा है, जिसका औसत मान 4.2 से ऊपर है। सभी आश्रित चरों में सहमत्ता व असहमत्ता के मूल्यों के बीच एक सार्थक अंतर पाया गया है, जहां काई – स्कवायर का मान 0.05 से नीचे पाया गया है।

VII. संदर्भ सूची

I. Goel, S., Dwivedi, R., & Sherry, A. M. (2012). Critical factors for successful implementation of E-governance programs: a case study of HUDA. *Global Journal of Flexible Systems Management*, *13*, 233-244.

II. Kumar, P., Kumar, D., & Kumar, N. (2014). E-governance in India: Definitions, challenges and solutions. *arXiv preprint arXiv:1411.1876*.

III. P.Muralidharan (2010),“E-governance – A service delivery mechanism for effective administrative system”, *Indian Journal of Development Research and Social Action,* Vol. VI, No. 12, January- December, pp. 329-335.

IV. Sharma, T., Mangalaraj, G., & Natarajan, V. S. (2016). E-governance in developing countries: a case study of E-Disha initiative in the Indian state of Haryana. *International Journal of Indian Culture and Business Management*, *13*(1), 93-110.

V. Yadav, K., & Tiwari, S. (2014). e-Governance in India: Opportunities and challenges. *Advance in Electronic and Electric Engineering*, *4*(6), 675-680.

VI. https://informatics.nic.in/uploads/pdfs/b7831060_1Haryana.pdf.